फिलैटेलिक सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 11.05.1992 को विचारार्थ रखा गया था तथा बाद में फिलैटेलिक सलाहकार समिति की उप-समिति ने इस प्रस्ताव की जांच की थी। तथापि, समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं के निवास पर मीटर लगाया जाना

3629. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं के निवास में मीटर लगाने का विचार रखती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ताओं के अहाते में मीटर संस्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की गई, परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

डाकियों द्वारा अपने घरों से चलाए जाने वाले डाकघर

3630. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में कितने-कितने डाकघर हैं और उनके जिलावार नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त डाकघरों में से ऐसे कितने डाकघर हैं जहां केवल डाकिया ही सारा कार्य देखता है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे डाकघर घरों में चलाए जा रहे हैं और वहां डाक सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की डाक-तार सेवा को सुचारू बनाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में बचत खातों में गड़बड़ी

3631. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में बचत खातों में गड़बड़ी की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए है ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हों?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्पीड पोस्ट सेवा

3632. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों की राजधानियों में स्पीड पोस्ट सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किन-किन राजधानियों में यह सेवा आज की तारीख तक विद्यमान नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नहीं। सभी राज्यों की राजधानियों की स्पीड पोस्ट सेवा के राष्ट्रीय नेटवर्क अथवा प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा कवर किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं हेतु नई नीति

3633. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक सेवा हेतु कोई नई नीति बनाई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) डाक विभाग देश में डाक सेवाएं सुलभ कराने की नीति का निरन्तर अनुसरण करता आ रहा है, जिसमें काउंटर सेवाओं के साथ-साथ मेल प्रोसेसिंग व वितरण भी शामिल है। काउंटर सेवाएं डाक नेटवर्क का नियमित विस्तार करके सुलभ कराई जाती हैं जबकि मेल प्रोसेसिंग तथा वितरण में सुधार कार्यविधियों को युक्तिसंगत बनाकर, उपयुक्त परिवहन प्रणालियों को अपनाकर, प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन तथा बेहतर प्रबन्ध के जरिए किया जाता है। इसी मूल-नीति को जारी रखते हुए अधिक कार्यकुशल, दोषरहित तथा उत्तरदायित्वपूर्ण काउंटर सेवा के माध्यम से अधिक ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अब नए प्रयास शुरू किए गए हैं। इन उद्देश्यों को कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनों, सेवा-शर्तों के अध्ययन द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाकर तथा उन्नत कार्य-वातावरण के माध्यम से प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। आधुनिकीकरण का यह कार्यक्रम कार्य का स्वच्छ तथा आत्मीय वातावरण प्रदान करके कर्मचारी संतुष्टि को भी संवृद्ध करेगा तथा ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं सुलभ कराने में विभाग को समर्थ बनाएगा।

मेल प्रोसेसिंग तथा वितरण के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी तथा महानगरों और देश के राज्यों की राजधानियों के बीच पिन कोड अंकित डाक की भारी मात्रा की प्रोसेसिंग व वितरण के लिए सुव्यवस्थित चैनलों की व्यवस्था करना है। इन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मेट्रो चैनल, राजधानी चैनल तथा बिजनेस चैनल शुरू किए गए हैं। डाक की भारी मात्रा को निपटाने के लिए ऐसी कारगर व्यवस्था से ऐसी संभावना है कि इस प्रणाली की बोझिलता दूर होगी और डाक सेवा को अपने सभी प्रोदत्ताओं के लाभ के लिए सुचारू रूप से कार्य करने में समर्थ बनाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक से बैंक ड्राफ्टों और चैकों की चोरी

3634. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बड़ौदा और अन्य स्थानों में डाक से बैंक ड्राफ्टों और चैकों की चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1994 से 30 जून, 1994 तक की अवधि के दौरान ऐसी कुल कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) जी हां। केवल अहमदाबाद में 1.1.94 से 30.6.94 तक की अवधि के दौरान 6 अलग-अलग डाकघरों के डाकियों के थैलों में से पंजीकृत वस्तुओं सहित डाक वस्तुओं की चोरी के दस मामलों की सूचना मिली है।

(ग) अलग-अलग डाकियों के थैलों में से, बदमाशों द्वारा पांच मूल्यदेय वस्तुओं, सात मनीआर्डर फार्मों, एक पार्सल और 581 पंजीकृत पत्रों की चोरी करने की रिपोर्ट मिली है।

(घ) इन सभी मामलों की अहमदाबाद के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नवरंगपुरा पुलिस ने एक बाहरी पोस्टमैन सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जाँच-पड़ताल की जा रही है।

Linking of villages with cities and state capitals by telephone in Gujarat and Maharashtra

3635. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of COMMUTATIONS be pleased to state:

(a) the district-wise number of villages in Gujarat and Maharashta particularly in the Kachh regions which have been linked with cities by telephone and S.T.D. facilities upto 31 st March, 1994 under the scheme of linking villages with cities and State capitals by telephones;

(b) the district-wise number of villages proposed to be linked-up during 1994-95 and 1995-96 with modern telephone exchange equipments;

(c) the number of telephone exchanges set up by the 31st March, 1994, district wise in these States; and

(d) the number of telephone exchanges proposed to be set up during 1994-95 and 1995- 96 district-wise?